उत्तरांचल शासन लूचना प्रौद्योगिकी अनुमाग संख्याः 367 /XXXIV / 170-सू०प्रौ० / 2006 देहरादून : दिनांकः 2 | अगस्त, 2006

विज्ञाप्त / नीति

उत्तरांचल राज्य पूर्णतह अकीकृत करने, एक नेटवर्क स्थापित करने जहाँ सूचना की पहुंच एवं प्रवाह समाज के समस्त वर्गों के मध्य सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी की प्रभावी आधारभूत सुविधाओं के माध्यम से समर्थ कराने, राज्य के आर्थिक विकास को आगे बढ़ाने, नागरिकों को उच्च गुणवत्ता का जीवन प्रदान करने तथा रोजगार के समुचित अवरार उपलब्ध कराने आदि हेतु संलग्न "सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी नीति, 2006" को प्रख्यापित करने की श्री राज्यपाल महोदय सहबं स्वीकृति प्रदान करते हैं।

संलग्नक ; यथोक्त।

(संजीव चोपड़ा) सचिव।

पृष्ठांकन संख्याः 367 (1)/XXXIV/170-सू०प्रौ०/2006, तद्दिनाकित। प्रतिलिपि निम्नलिखित कॉ संघूनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. सचिव, मा० मुख्यमंत्री, उत्परागत ।

- 2. समस्त निजी सचिव, मा० मंत्रीगण उत्तरांधल सरकार।
- 3. स्टाफ आफ्रीसर-मुख्य सचिव, उत्तराचल शासन।
- 4. स्टाफ आफीसर-अपर मुख्य राविय, उत्तरांचल शासन।
- अवस्थापना विकास आयुक्त, उद्योगवल शासन।
- 6. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उतारावल शासन।
- मण्डलायुक्त, कुमाऊँ / गढ्याल होच, उत्तरांचल ।
- समस्त जिलाधिकारी, जत्तरांच्याः
- समस्त विनागाध्यक्ष / कार्यालयाध्यक्ष, उत्तरांचल ।
- 10. निदेशक, आई०टी०डी०ए०, उरपरापल ।
- 11. प्रबन्ध निदेशक, सिडकुल/हिल्डान उत्तरायल।
- 12. सविवालय के समस्त अनुभाग।
- निदेशक, एन0आई0सी0 सक्तिवालय परिसर, देहरादून को उत्तरांवल की वेवसाईट में रखने हेतु।
- उप निदेशक, राजकीय गुढणाताय राजकी, उत्तराचल को इस आश्रम से की संलग्न नीति को असाधारण गजट में प्रकाशनार्थ।
- 15. गार्ड फाईस।

आज्ञा से

(संजीव बोपडा) संविव। सूचना एवं संचार प्रोगानिक उत्तरांचन सरकार

सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, उत्तरांचल



अनुक्रमणिका

I- प्रस्तावना
II- दृष्टि एवं लक्ष्य
III- उद्देश्य
(अ) सूचन एवं संचार प्रौद्योगिकी के माध्यम से सु-शासन
(य) सूचना प्रौद्योगिकी के अंगीकरण एवं ज्ञान-उद्योग को आकर्षित कर त्वरित औद्योगिक विकास
(सं) ज्ञान-समाज का निर्माण:
IV- समर्थंक नीतियाः
(अ) प्रभावी सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी आधारभूत सुविधाओं का निर्माण
(क) राष्ट्रीय सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी नीतियों का समर्थनः
(ख) प्रौद्योगिकी— संरचना एवं भानक
(ग) आधारभूत-सुविधा प्रबन्धन
(घ) राज्यव्यापी अंकीय भण्डार—आंकड़ा केन्द्र— सूचना जीवन—चक्र प्रबन्धन1
(ढ.) नेटवर्क / संचार अवस्थापना
(व) कार्य प्रक्रमण प्रवाह- शासकीय प्रक्रमणों का पुन:- अभियंत्रण1
(स) सरकारी सेवाओं का स्वरूपः
(द) घेनल (ढाँचा) सम्बन्धी कार्य-नीतिः1
(य) मानव कार्य—कुशलता का विकास
(र) न्यायिक ढॉचा और तृतीय—पार्टी सेवा सम्बन्धी ढॉचा1
(क) सुरक्षितताः!
V- प्रतिरथर्द्धात्मक नीतियाँ
VI- स्थीकारात्मक मीतियाँ
VII- जन्नाते नीतियां
VIII- निष्पादक नीतियाँ
(अ) सूचना प्रौद्योगिकी सलाइकार समिति
संलग्नक 'अ': सूचना प्रौद्योगिकी:





उत्तरांचल शासन की सूचना एवं संचार प्रौद्योगिक नीति, 2006 का लेखा-पत्र

1- प्रस्तावना

उत्तरांचल राज्य का गठन 09 नवम्बर 2000 को तत्कालीन उत्तर प्रदेश के उत्तरी भाग के पृथकीकरण से हुआ। उत्तरांचल राज्य हिमालय पर्वत श्रखला का पवर्तीय एवं तराई क्षेत्र है, जो 53,483 वर्ग कि0मी0 में फंला है (जिसमें से लगभग 88 प्रतिशत पवर्तीय है) और जिस की जनसंख्या लगभग 85 लाख है। देवों की यह भूमि प्राकृतिक संसाधनों जैसे जल, वन, संपदा, नदियों, हिम—नदियों एवं पहाड़ी चोटियों के लिए प्रख्यात है।

- 1. राज्य के नागरिकों के जीवन की गणवला सुधारने हेतु त्वरित सामाजिक एवं आर्थिक विकास, शासकीय निर्णयों में पारवर्शिता, समस्त उपयोगकर्ता—समूहों द्वारा सूचना प्राँद्योगिकी को त्वरित गति से अपनाने हेतु उत्तरांचल शासन द्वारा सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी की पूर्ण शक्ति का प्रयोग प्रस्तावित हैं। उत्तरांचल शासन का यह प्रयास है कि एक आदर्श "ई—समाज की रचना दक्ष, सेवा—केन्द्रित, मूल्य—उपयोगी, सूचना नेटवर्क (जाल) एवं पर्यावरण के प्रति संवेदनशील स्वरूप के साथ वर्ष—दर—वर्ष प्रगति करें।
- इस दस्तावेज का उद्देश्य राज्य के सम्पूर्ण वास्तविक विकास हेतु सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के प्रभावी स्वरूप एवं प्रबन्धन हेतु एक ढांचा नीति प्रदान करना है। यह नीति दस्तावेज, उत्तरांचल शासन की नवीन औद्योगिक नीति 2003 एवं जो औद्योगिक विकास विभाग के उद्योग निदेशालय एवं उत्तरांचल लघु—उद्योग विकास विभाग दारा विभोधित की गयी है का एक विस्तरित दस्तावेज बनेगा।

II- दृष्टि एवं लक्ष्य

उ. दृष्टि यह है कि उत्तरांचल राज्य पूर्णतः अंकीकृत हो— एक नेटवर्क समाज हो जहां सूचना की पहुँच एवं प्रवाह समाज के समस्त वर्गों के मध्य सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकों की प्रभावी आचारभूत सुविधाओं के माध्यम से समर्थ कराते हुए राज्य के

fm





आर्थिक विकास को आगे बढ़ाना, जिसके फलस्वरूप नागरिकों को उच्च गुणवत्ता का जीवन प्रदान करना है।

- मूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी क्षेत्र की इन प्रारम्भिक कार्यवाही का एक मुख्य परिणाम रोजगार उत्पन्न करना है। उत्तरांचल राज्य के उच्च साक्षरता दर (राष्ट्रीय औसत से ज्यादा) के परिपेक्ष्य में सरकार ने बेरोजगारी कम करने का लक्ष्य निधारित किया है। इस दिशा में सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवाओं को उत्तरांचल में उधम में स्थापित करने हेतु प्रोत्साहित किया जायेगा। उत्तरांचल में रोजगार उत्पन्न करने का फोकस अर्थ व्यवस्था के सेवा सेक्टर में रहेगा।
- 5. सूचना प्रीद्योगिकी के इन मध्यवर्तनों से शासन की योजना विभिन्न बटवारों जैसे की अंकीय भिन्नता, आर्थिक भिन्नता, साक्षरता भिन्नता एवं सामाजिक भिन्नताओं को कम करना भी है। ज्ञान द्वारा संतलक का निवाहन करने और सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकी के अपनाने से यह भिन्नता धीरे-धीरे समाप्त हो जायेगी।

॥- उद्देश्य

- म्यूबना प्रौद्योगिकी को प्रोत्साहित किये जाने का उद्देश्य केवल शासन स्तर पर प्रबंधन एवं निर्णय—सहायता—तंत्र के रूप में ही नहीं वरन् शासन की प्रक्रिया एवं प्रणालियों को पुन:—माबित किया जाना भी होगा, जिससे की नागरिकों के प्रति एक पारदर्शी, संवेदनशील एंव क्रियात्मक सरकार का गठन सम्भव हो।
- नागरिकों के भौतिक—जीवन में वांक्षित सुधार सूचना प्रौद्योगिकी के विभिन्न अवयवों
 को सरलता से उपलब्ध कराते हुए सुनिश्चित करना।
- iii. निजी क्षेत्र के प्रयासों को प्रोत्साहित करना जिससे की विश्व-स्तरीय सूचना प्रौद्योगिकी अवस्थापनाओं का विकास हो सके और नागरिकों, उद्योगों एवं शासन की आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके।
- iv. सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग से संबंधित आवश्यक मानवशक्ति का 'विकास एवं विस्तारीकरण एवं सूचना प्रौद्योगिकी को त्वरित गति से स्कूलों, कॉलेजों और अन्य

Gr



शिक्षा-संस्थानों तक ले जाना जिससे की युवाओं को सम्बंधित निपुणता प्राप्त हो सके और वे इस क्षेत्र में रोजगार पाने के लिए सक्षम होवें।

प्रचना प्रौद्योगिकी संबधी उद्योगों को प्रोत्साहित करना जिससे की सूचना प्रौद्योगिकी सकल घरेलू उत्पाद का वाहक बने। इसके लिए राज्य को एक अच्छे सूचना प्रौद्योगिकी-गंतव्य के रूप में विकसित करना, जिससे युवाओं के लिए रोजगार के अवसर इस क्षेत्र में उत्पन्न हों और उनकी आय क्षमता में बढोत्तरी समव हो सके, साथ ही साथ इस क्षेत्र में निर्यात एवं घरेलू वित्त क्षमता की उपरिथति को तलाशना।

(अ) सूचना एवं सचार प्रौद्योगिकी के माध्यम से सु-शासन

- 6. इस तथ्य की पहचान करते हुए की सु-शासन मूलतः मानव क्रियाओं और प्राचीगिकी का मिश्रित प्रमाव है, उत्तरांचल सरकार इस ओर प्रत्यनरत रहेगी की "नवीनतम् प्रौद्योगिकी" का परिनियोजन हो और इसका समर्थन इष्टत्म प्रशासनिक क्रियाओं, नागरिकों और व्यापार का शासन से सरल अंतराफलक, नागरिकों में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के प्रमावी उपयोग हेतु पर्याप्त प्रवीणता के निर्माण से पुनिश्चित किया आयेगा। राज्य की ई-गवर्नेस नीति का उपयोग नागरिकों को सशक्तिकरण प्रदान करने के औजार के रूप में किया जायेगा।
- 7. अतः सरकार का एक ध्येय है कि राज्य एवं केन्द्र के विभिन्न विभागों के मध्य समन्वय, सहयोग एवं सूचना का अनुकलन हो। इससे नागरिको, व्यापार एंच अन्य सरकारी विभागों को तत्पर—सेवा, आसान शासकीय—क्रिया एवं विभिन्न सरकारी विभागों को अन्तः सम्बन्धी सेवाओं के संग्रहण से प्रदान की जा सकेगी।
- (ब) सूचना प्रौद्योगिकी के अंगीकरण एवं ज्ञान—उद्योग को आकर्षित कर त्वरित औद्यौगिक विकास

राज्य का आर्थिक विकास औद्यौगिक गतिविधियों में वृद्धि, मूल्य-वर्धित व्यापार में वृद्धि और बहुमूल्य प्राकृतिक संसाधनों से चलित है। राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का बड़ा भाग वर्तमान में सेवा सेक्टर (खंड) से आता है और यह राज्य में सेवा-प्रधान अर्थव्यवस्था स्थापित करता है। राज्य की अर्थव्यवस्था के अन्य वाहक





कृषि, उद्यान, आषधिय/हर्बल सम्पदा, जल-विद्युत, पर्यटन, सूचना प्रौद्यौगिकी एवं बायो प्रौद्यौगिकी है।

- शासन की यह नीति रहेगी कि राज्य में सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग में निजी पूँजी —िनवेश हो। सरकार विश्व—स्तरीय आधारमूत सेवा में मैत्रिक प्रशासनिक—ढांचा, प्रमुख उद्योगपतियों की नीति—निर्धारण ढांचे में सहभागिता सुनिश्चित कर एवं वित्तीय व गैर—वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करते हुए एक समर्थक का किरदार अदा करेगी एवं उत्तरांचल को सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग का आकर्षक गन्तव्य बनायेगी।
- 9. वित्तिय ग्रेस्ट्राहन नवीन औद्योगिक नीति 2003 में इंगित है (सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग से सम्बन्धित खण्ड संलग्न 'अ' पर प्रस्तुत है।) तथा रू० 50 करोड़ से ज्यादा/ बड़ी परियोजनाओं हेतु विशेष प्रोत्साहन माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में गठित समिति में तथ किये जायेंगे।
- 10. शासन विभिन्न हार्डवेयर, साफ्टवेयर एवं सूचना प्रौद्यौगिकी समर्थ-सेवाओं को राज्य में उद्योग स्थापित करने हेतु प्रोत्साहित करेगी, सामान्यतः भी उत्तरांचल में व्यापार स्थापित करने और बहुमूल्य विविधताओं का अन्वेषण करने हेतु उद्योग को आकर्षित किया गया है।

गैर वितिय प्रोत्साहनः

- सरकार राज्य में एक निवेशक मैत्रिक-पर्यावरण को विकसित करेगी और निम्न सुनिश्चित करेगीः
 - सूचना प्रौद्योगिकी उद्योगों को प्राथमिकता के आधार पर भूमि उपलब्ध कराना।
 - सूचना प्रौद्योगिकी उद्योगों को नियमित रूप से एवं निरंतर विद्युत उपलब्ध कराना।
 - स्वविद्युत उत्पाद को उत्साहित करना एंव इस हेतु विद्युत भार (duty) पर
 पूर्णरूपेण छूट।

bon





- राज्य के वितीय संस्थानों द्वारा ऋण उपलब्ध कराए जाने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र को प्राथमिकता रहेगी।
- 5) विशेष प्रयासों के द्वारा उच्चकोटि की सामाजिक अवस्थापनायें यथा स्कूल, आवास, स्वास्थ्य, मनोरंजन इत्यादि सुविधाओं को सूचना प्रौद्योगिकी स्थलों पर विकसित करना।
- 6) सूचना प्रौद्योगिकी विभाग में एकल-पटल की स्थापना जिसके माध्यम से सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग को शासन के विभिन्न विभागों का अनुमोदन एवं अनापत्ति (Clearance) प्रदान कर एक समर्थक प्रशासन उपलब्ध कराना।

आधारभूत सुविधाओं का समर्थनः

- 12. राज्य का यह यत्न रहेगा की इन उच्च प्रौद्योगिकी उद्योगों को अपनी निम्न शक्तियों यथा— मनोहर स्थल, प्रतियोगी भूमि मृत्य, योग्य मानव संसाधन, सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में निपुण कार्यबल, अगसक्रिय प्रशासन, आधारभूत सुविधाओं का विकास जिससे वायु, रेल, सडक एवं दूरसंघार संयोजकता का उत्तोलन कर आकर्षित किया जाये।
- 13. उत्तरांचल में सूचना प्रौद्यौगिकी आधारित उद्योग को आकर्षित करने के लिए राज्य का एक योजनाबद्ध पथ पर है तथा इस क्षेत्र के निवेश को प्रशासन की दक्षता सुधारने और नागरिक व शासन के मध्य एक सच्ची लोकतांत्रिक सामन्जस्य स्थापित करना है।
- 14. सरकार अपनी योजनाबद्ध रणनीति के अन्तर्गत उद्यमशील रूप से संभावित निवेशकों को चिन्हित करेगा एवं उनके संदर्भित व्यापार हेतु उत्तरांचल की उपयोगिता प्रस्तुत करेगा।
- 15. सरकार ज्ञान—उद्योग को उत्तरांचल में आकर्षित करने के प्रयास करेगी इस हेतु सूचना प्रौद्योगिकी शिक्षा के लिए आवश्यक आधारमूत सुविधा उपलब्ध करायेगी।
- सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि नवीन उद्योग स्थापित करने हेतु समस्त अनापित
 (Clearance) शीर्प पायगिकता सं प्रधान कर दी जाते।





- 17. सरकार अग्रणी अन्तराष्ट्रीय सलाहाकार फर्मो एवं विश्व—स्तरीय निवेश प्रोत्साहन एजेंसियों से गठबंधन पर विचार करेगी, जिससे एक सूचना संचार, प्रौद्योगिकी का सुखावह पर्यावरण स्थापित हो सके।
- 18. सूचना प्रौद्योगिकी पर कार्यशालाओं / विमर्शगोष्ठीयों का सरकार सर्मथन करेगी। इन कार शालाओं से सूचना प्रौद्योगिकी उत्पादों को स्थापित करने से होने वाले लाभ जैसे की दक्षता में सुघार, उत्पादकता में वृद्धि, प्रतिस्पर्धात्मकता का विकास एवं विश्व स्तरीय छाप की अभिज्ञता बढ़ाना है।

(स) ज्ञान-समाज का निर्माणः

- उत्तरांचल एक ज्ञान-समाज स्थापित करने के लिए प्रयास करेगा जो राज्य में सूचना के व्यापक उपयोग से परिलक्षित होगा।
- rv- समर्थक नीतियाः
- (अ) प्रभावी सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी आधारभूत सुविधाओं का निर्माण
- (क) राष्ट्रीय सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी नीतियों का समर्थनः
- 20. भारत सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के विभिन्न नवीन प्रयास यथा— राज्य-स्तरीय क्षेत्र नेटवर्क (SWAN), ब्राण्डवैण्ड नीति, सामान्य सेवा केन्द्र (Common Service Centre—CSCs), राज्य आंकड़ा केन्द्र (SDC), राष्ट्रीय ई—गवर्नेन्स योजना (NeGAP), इण्टरनेट प्रक्षेत्र नाम (IN) के क्रियान्वयन हेतु जो नीतिसंगत ढॉचा से सम्बन्धित है का क्रियान्वयन राज्य में भारत—सरकार के दिशा—निर्देशों पर किया जायेगा। केन्द्र के समर्थन के अलावा जो अतिरिक्त आधारभूत सुविधाओं की आवश्यकता होगी वह राज्य सरकार सुनिश्चित करेगी।

(ख) प्रौद्योगिकी— संरचना एवं मानक

1- संरचना

21. ई—गवर्नेन्स की संरचना के ढाँचे के विकास में सेवा—सृजन एवं सेवा—वितरण करने वाले विभिन्न पक्षकार जैसे की सेवा—जिज्ञासु, सरकारी सेवा तथा अन्य





तृतीय-पक्षीय सेवा-प्रदाता यथा अभिप्रमाणन एवं भुगतान-गेटवे सेवायें, नेटवर्क सेवा-प्रदाता, आधारभूत सुविधा प्रबन्धन सेवाओं को देय मान्यता दी जायेंगी। इस से इन प्रकारों के मध्य व्यवधान रहित अंतराफलक दक्ष एवं सुगम सेवाओं को सृजित एवं प्रदान किया जा सकेंगा जो की प्रभावी सार्वजनिक निजी सहमागिता/ प्रतिदर्श के माध्यम से हर समय (24 x 7) गुणवत्ता-पूर्ण सेवा सुनिश्चित करेगा।

2- मानक

- 22. राज्य ने केन्द्र द्वारा अंगीकृत किये जा रहे ढाँचे पर आधारित आंकड़ों के मानक तैयार किये हैं, जिनका शासन द्वारा वर्तमान की ई—गवर्नेन्स परियोजनाओं में पालन किया जा रहा है तथा मविष्य में सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार द्वारा निर्गत ई—गवर्ने स मानक, जो की अर्त्रा—प्रवालन, आंकड़ों, मेटा—आंकड़ों से सम्बन्धित होंगे, के अनुपालन हेतु सरकार आदेशित करेगी।
- 23. इसके अितरिक्त सरकार विशेष सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी मानकों, जो की मान्यताप्राप्त अन्तराष्ट्रीय संस्थाओं जैसी की IEEE', IETF W3C', ISO', CMM' आदि द्वारा अनुमोदित है के अंगीकरण पर दृढ़ रह सकती है।
- 24 उत्तरींचेत सरकार तकनीकी रूप से Neutral है किन्तु इसका एकीकरण (Integration) करने के लिए आवश्यक है कि कोई भी साफ्टवेयर पारवर्शी मानक (Open Standards) पर आधारित हो तथा उनके एकीकरण मानक (Integration Standards) परिभाषित (defined) हो। अतएव उत्तरांधल सरकार पारवर्शी मानक के आधार पर कार्य करेगी।

ानेटफार्म चयन हेतु, उत्तरांचल सरकार के लिए, मुख्य मुद्दा कुल परिप्रेक्षित स्वाभित्व व्यय (Total Long Term Cost of Ownership: TLCO) है ।

bon

¹ IEEE इलेक्ट्रीकल एट इलेक्ट्रीनिक्स इन्जीनिक्स्रिय संस्था

² IETF इन्टरनेट इन्जीनियरिय कार्य-बल

¹ W3C वर्ड—वाईड-देव कन्सोएसन

⁴ ISO अन्तर्राष्ट्रीय मानक संगठन

³ CMM केपेबिलिटी मेचुरिटी गॉडल



3



(ग) आधारमूत -सुविधा प्रबन्धन

भूचना सन्तर प्रोद्योगिकी की अधारभूत सुविधाओं के विभिन्न घटकों के स्थापित होने के नद आधारभूत सुविधा प्रबन्धन के कार्य को बाह्य संस्था से कराया जाना एक आवश्य अवश्य बन जारा। आधारभूत सुविधा प्रबन्धन तन्त्र सूचना एव सचार प्रचोग की की आधारभू सुविधाओं यथा आकड़ा केन्द्र, नेटवर्क (स्वर एव आकड़), ''कट प एव सहाय () उसक सचालीकरण का प्रबन्धन करेगा।

- 25 उत्तराधाः सन् की सूचना प्राद्यागिकी आधारभूत सुविधाओ पर चलन वाले अतिआकः, गाँगिकणान आर एक इवाल्ट में स्टीर किये जा रहे अभिलेखों की व्यापार-निर्नार गाँच आवद बहाली प्रणाली स्थिपित होगी जिससे की प्राकृतिक अथवा २ प वृत्तिक अपवा की गटना में 99.90 प्रतिशत अप—टाईम सुनिश्चित होगा। आधारभूत स्वाधा प्रकर्भन तथ्य पृद्धभन्य पर विभागा एवं सद्वा अभिगमन प्रदाताओं की 24X1 राज अका श्री स्वार्थ में विद्या स्वास सुनिश्चित करेगा।
- अधारणु अक्षा प्रक्रिया प्रकार प्रकार प्रक्रिया जहां तक समय होगा बाह्य प्रकार का का का का का का का स्वाक्ष्य प्रकार का स्तर स्वीकृति विधिवत दिन प्रकार अपन्य का स्वाक्ष्य और क्रियान्वयन जी की सार्च का का का का किया का स्वाक्ष्य अधार पर स्थिप हों का स्वानत करती है।

(घ) राज्यव्यापी अ तीय मण्डार- आकका केन्द्र सूचना जीवन चक्र प्रबन्धन

- 27 राज्य रा ा अन्द्र एवं ए अन्य राज्यों / कंन्द्र के आकड़ा केन्द्रों से अन्ती प्रकारने नाम सरकार विद्यानिर्देशों के अनुरूप होंगा।
- 28 राज्य व गिरान विभागां र राजित हान वाले आकड़ों के प्रक्षेपित सचय के अनुरूप के कर्ण कन्द्र को पूर्ण अन्य सन्यायाणी अकीय मण्डार के रूप में संवर्धित किया न का यह मण्डार सरकारी आकड़ों को ग्रहण संग्रहित सूचक एवं सुरक्षित कर पुन वितरण करेगा अन्यक्त उत्तर चल पहली सरकार होगी जो इस प्रकार के भविष्य यद गम्बन्धी मानक गांधारित अकीय भण्डार को क्रियान्वित करेगी,





29 सूचना का साथ के साथ मन्य सूचना कितनी जल्दी और किस लागत पर उपयोगहर प्रश्न पर रूप कथ करायी नायं तथा सूचना को कब तक मिटाने से पहले रन्द व र इस सब का समावेल सूचना जीवन चक्र प्रबन्धन (ILM) में किया ज देगा। मां चक इं में प्रणा नी पर डालं जायेंगे उनको अभिगमन नियमो धारण जरूरतो 🚁 र अनुभवनो पर आ राहेल एक श्रणी प्रदान की जायेगी .

(ड.) नेटवर्क / संचार अवस्थापना

- 33 नेत्वक १ ६१ ना एक अं रना अधारभूत आवश्यकता है जिस पर ई गवर्नेन्स के समरन प्राप्त र नाकु होता चया स्तरीय क्षेत्रीय नेटवर्क (SWAN) के द्वारा इस रुवर न वा थापना है। अन्त किया नायगा। राज्य की भौगोलिक र ित वया हुए लाम न- इना नटवर्क स्थापित करना होगा वा तोर रह ता करों का वाक्षा असम नहां की साथ हो सकी। राद्य 🔻 🧸 त्र भी प्र 🔻 २ वाधेत मास्त सरकर के विश्वनिर्देशों का म र न । । । किसा त सर धर से इस कर कहामति एव सहायता Altha art का कि एक मिले अन्य मि वि एवं सार्व तिनेक नेटवर्क को व गार्ट है । इन व भाग घर पाला । वहाई जा सक और प्रतिसंदर्श के माध्यम से दामों को सामर्थ में रखा जा सके।
- · यर देव अनीना के के स्वारत नरती जो उत्तराधल में नेटवर्क की अब भार । अप तभार । असरकार ने असरकार ने असरकार ने असरकार ने स्वाधित करने हेत् प्रेरित नि भिर को गोलिंगिला से अनापनियाँ प्रदान करने के उद्देश्य से "रास्ते के अधिकार" नीति को प्रोत्साहित करती है।
- कम्युटर ्व इप्ट नर का प्रदेश आवारभूत सुविध भी के सूजन का महत्वपूर्ण 32 हिस्सा दें अधार के एर कर कर वह परना समयबद्ध तरीके से प्रदान की नायमा । १८ खाउ में बााव नेत् उत्तराचल ने अग्रसक्रिय कदम उठाये हैं। परियोजनः अना कर्ष के अन्तरात राज्य न सार्वजनिक क्षेत्र के बैकों से करार कर रारकारी (मन, रेटा) हिंदा को कम्प्यूटर क्रय हेतु कम व्याज/ आसानी से



석충

43

3

230

20

270

3

113

13

(3)

119

.3

413

3

100

4

13

43

-15

42

13

23

43



मुकता राजे वाले ऋण के रूप में उपलब्ध कराया है। इण्टरनेट सेवा प्रदाता राज्य में क्रियाशील है।

- 33 प्रभागं ा ह्यानिक अभिलख प्रवन्धन (eRM) निग्न का समर्थन करेगा
 - प्रतिक इस त्यांनिक भिराय को आसानी और गति से पुन प्राप्त करना,
 - अन्त प्रचातनो के से द दक्ष संयुक्त कार्य सूचन। का आदान प्रदान एवं अन्त प्रचातन,
 - ि र नीए ए प्रमाण त्युधना का पूर्व-कार्यवाही एवं निर्णयों के मृत्याकन से

 सन्दान ता पर रण को सम्मितित रूप ना प्रस्तुत कर साक्ष्य आधारित नीति

 निर्णारण में सहयोग,
 - .. व हे हेट (र . र) व क मध्यम री आकड़ों क रक्षण सिद्धान्तीं एव जन्म १ हेट व व हे हो। तथा सूर्या स सम्बन्धित अन्य तीति -विधानों को इयन्धन
 - e । १ माराज्य राष्ट्रान् । १ मन्य विश्वसमीय सृचनाओं का आदान प्रदान, विष्कर्षण और साराश के साथ ज्ञान-प्रबन्धन ।

(य) कार्य प्रक्र नण प्रवाह शासकीय प्रक्रमणों का पुनः अभियत्रण

अंतराक्ष्मक के सरलीकरण का विवेधक तथ है निसंसे नागरिक सरकार के

34. गल्य दे उत्तर के कि स्व क्यांन्य प्रदान करने हेत् प्रक्रमण के स्वचलनीकरण मारा को प्रदर्भ की प्रदर्भ की प्रदिश्य में सम्भीर प्रयास वाधित होगा। वा ता किया पूर्व भयन्त्रण की दिशा में सम्भीर प्रयास वाधित होगा। वा वा वा व्यक्ति अपने में क मुख्य चुनोती है को निर्णय प्रक्रिया के स्वचलनीकरण को एक स्तर तक सुगमता प्रदान करता है।



49

49

10

4

鶴

13

20

-15

100

3

الرب

3

1 1/19

50

3

13

· *3

4

13

. 3

~~ 码

(19)

2 3

5---



- 35 राज्य है सामाण एवं सुदूर है ब जो की महंज दूरी की वजह से शासकीय सेवाओं की उपानका सं अन्याधिकार प्राप्त है को ई गवर्नेन्स प्रदान करने के लिए विशेष फोकर रखा जायेगा।
- 36 पून भन्यानेश्वत शासकीय प्रक्रमण और नागरिकों की अपेक्षा अनुसार राज्य के सभी विभागों का कम्प्यूटरीकरण होगा।
- 37 शिवन र जरुरी प्रशारमिक सुधार लायेगी जी पुन अभियन्त्रण मूल्य आधार रण दिसन विभाग है पार अमूर्त सामान्य क्रियाशील तत्वों को शामिल करें के हैं पासव हैं ई-नुगतान हैं रिटर्न ई अनुमोदन आदि। यह सब रिद्र हैं अनुमोदन आदि। यह सब रिद्र हैं अनुमोदन आदि। यह सब दिद्र हैं अनुमोदन आदि। यह सब

(स) सरकारी वेवाओं का स्वरूप:

- का रक्त के का का का स्थान प्रतिशिक्त के आधार पर उपलब्ध कार्च की का का सकता है जी इस प्रकार हैं-
 - क . रान प्रतः (२)५ बाद (३) लेख देन एव (4) एकीकरण
- 41 प्रता १ वा गार प्रशास इसका म्रह्मत उपयोग निम्न के लिए किया जायेगा—

 - प्रतिय राज्य रसर्घ क्षत्राय स्थानीय अधिकारिया के नाम पते ई--मेल व दूरभाष नम्बर ऑनलाईन उपलब्ध कराना।

bw



dig

3

10

20

3

9

19

1

Ð

19. 19



- कार की यो तना बराट व्यय व निष्पादन आख्या का विवरण ऑन लाईन उप नव्य कराना।
- न गरिको क निर्माल न कारी पर्याप्तरण सम्बन्धी, नागरिक व राज्य आदि से र ग नियत महत्वपूर्ण गण्यक निर्णयों की जानकारी ऑन-लाईन उपलब्ध व राना।

परकार हार. पालका कारी जा रही विविध प्रकार की सेवाओं की जिल्ल जानकारी प्राप्त करने का यह प्रवेश-बिन्दु है।

- 42 जन है अन्तर्भक्तिया स्वर्ध मिसाओं का अन्तर्ग उच्च स्तर है जिसमें नागरिक
 रूप के मान है राग्य स्वर्ध कर सकता है। अधिकाश विभाग सामान्य अतः
 है के कि महिर्म से राग्य चान अधिकारी कर्मचारी से सवाद करने की सुविधा

 का कि कि मान है। अधिकारी विभाग से सवाद करने की सुविधा
 जनकारी प्राप्त करना एक जदाहरण है।
- 41 स्कर्त त १ को भिरार तर है नेन-देन की आन-लाईन स्विधा उपलब्ध . १४ : ११ क्या नृत्यु प्रमाण धन्न उपलब्ध करान इसका एक खदाहरण है।
- 40 र । स्टब्स इंगर्ट ही दिशिन्न त्याओं का प्रान-आईन एकीकरण र र र र र र र र र र र र र का विभिन्न विभाग व सरधानों की सेवाओं की र र त र गान र र र रहत ही जाती है उद्योगों के लिए एकल पटल अनापत्ति व्यवस्था, इसका सूचक उदाहरण है।
- 45 राज्य र पत्न र पि अन्यस्ति स्तर पर प्रयुक्त अच्छी तकनीक का प्रयोग व क जा कि कर र तेन रवाओं की उपयुक्तता सुगम कर जिससे दूरस्थ क्षेत्रों व भाग र गणमान्य भी जा नो से सेवा का अभिगमन कर सर्वे ।
- 46 वह र त हार कि इन रव र का प्रयोग जनसामान्य **के संशक्तिकरण के लिए हो** ता के रावारों इत रहारिक मध्यम से शहरी व ग्रामीण सेक्टर में उपलेक्ष करायी जायें।

ban

.....



3

8

3

3

2

130

1

19

1

30

3

3

3

3



(द) चैनल (ढाँचा) सम्बन्धी कार्य-नीतिः

- 47 उत्तराहर अवश्य का निश्चित मत है कि ई गवर्नेन्स भाष्यम का एकमात्र ध्येय, नागरित के दर स्थान पर सेवाये उपलब्ध कराना है। यह व्यवस्था सरकर वागा पर निश्चरता कान्द्रत न हाकर नागरिकों की इच्छा व सुविधा पर निश्चर के करार का प्रयास होगा कि भौगोलिक विषमता के कारण प्रौद्योगिकी के प्रयास का वाली कि विनाइयों की दूर किया जाय।
- 48 'देश पाद र मा कि उपनोक्ताओं और प्रौद्योगिकी के बीच इस प्रकार अंतराफलक पा र प्रशासक शासन का स्विधाजनक महसूस हो। इस हेतु राप र पाद पाद उत्राण यथा कम्प्यूटर टेलीफोन टीबी, मोबाईल,
- ५२ न. (राज्यार 'दान न सम्मन्धित जनकारी आसानी से उपलब्ध हो इस - द्र परकार . सामान्य शवा केन्द्र के अनुरूप प्रत्येक गाँव में क्षा केन्द्र ((arramy harve (enire) स्थापित करने का प्रस्ताव है। करने के सामुदायिक स्थल होंगे।
- ा र प्राप्त करने में सहयोग प्रदान किया जायेगा।
- 52 सः किर्दात ि इत्यं कि ई सार्नन्य में इस प्रकार की प्रौद्यागिकी का राजा जिल्लासं सारो कि रूप सं अपग व्यक्तियों के लिए अंतरफलक आसान हो।

bn

**

2





(य) मानव कार्य-कुशलता का विकास

- 53 प्राची प्राची एवं सचार प्रौद्यागिकी के क्षेत्र में सम्भावित कार्य कुशलता विकसित करने १ इन प्रकार प्रयास करेगी जिससे रोजगार के अवसरों में वृद्धि हो सके प्रथा। प्राप्तिकों की क्षमता वृद्धि विशेषकर युवाओं सरकारी कर्मचारियों रायपात उद्योग कियों। प्राभीण समुदाय जिसमें महिलायें सम्मिलित हैं को स्वाना प्राप्तिकी उद्योग में रो गार के अवसर उपलब्ध हो सके।
 - ां भम । र्धन प्रयास के उन्तर्गत उत्तराधल सरकार का ध्येय सभी को पर हुन स्तु उत्तराधल सरकार ने 'आरोडी' परियोजना दान के किया अन्तर्गत सरकारी व सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक माध्यमिक किया में कम्प्यूनर प्रयोग राला स्थापित की गयी हैं। अन्ततीगत्वा घरणबद्ध तरीक से सभी विद्यालयों में आरोडी परियोजना को सम्पन्न किया जायेगा। भविष्य में इसे और सुदृढ़ किया जायेगा।
 - ्रा स्थानिक हमार विश्वविद्यालय परिसरों में कम्प्यूटर होते से वाला प्रतास करने हेते अपणी शिक्षण प्रदासाओं से उनके साथ हो सह स्थानिक ज्याने का प्रयास किया जा रहा है। इसके साथ ही सह विश्वविद्यालय परियोजना को अधिक स्था कि साथ के साथ हो हमार विश्वविद्यालय तथा महाविद्यालयों में शिक्षा प्राप्त कर रास से साथ हो साथ स्थान साथ हमार विश्वविद्यालय तथा महाविद्यालयों में शिक्षा प्राप्त कर रास से साथ प्राप्त तथा हान आधारित अर्थव्यवस्था (Knowledge Economy)
 - % र १० एक अधीन क्ष्मिन वर्धन का कार्य भारत सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी १९०० क दिला विर्देशा व पद्धीय ई गवर्नेन्स योजना के अनुसार किया जायेगा। इ. स. ६८० सरथाओं ५ आन्तरिक सरथानों के मध्य कार्यक्रम प्रवन्धन

6

のののののの

日 日 日 日 日 日

B

.9

150

100

3

3

130

. 30

13

华

*

3



金。當

9

10

4 651

3

41,0

10

100

200

43

111



ब्यापार किया पुन अभियावण प्रवन्धन परिवर्तन व वास्तुशिल्प- अभिकल्पना आदि सम्मिलित है।

(र) न्यायिक उ'दा और तृतीय-पार्टी सेवा सम्बन्धी ढॉचा

- 57. समर्थक न्यायिक ढॉचे का लक्ष्य निम्न होगा-
 - ् र वं निक भीते क मूल अक्ष्यों का सरक्षण यथा गोपनीयता, बचाव धारण क्षमता तथा सूचना तक सार्वजनिक पहुँच।
 - र वीय प्रक्रिया एवं स्टाय जो इलेक्ट्रानिक माध्यम से दी जा सकती हैं, से
 र स्टेन्स्त संवैधानिक अवस्थित करना प्राधिकार देना एवं बन्दोबस्त
 करना।
 - र जो उपलब्ध हर १ जाय और जो सरक्षित किये जाय उनके सम्बन्ध में
 गणगण्य निर्धारण १ वस्तामित्व के अधिकार निर्धारित करना।
 - तन नूचना ११ वि अध्यक्ता के अनुसार एक दूसरे विभागों के मध्य सहभाजन सुनिश्चित करना।
 - : गामकी इस अधारा शासकीय व्यवहार हेतु अधिकार क्षेत्री एवं कर्तव्या का निर्धारण।
 - ग रतन्त्र व र्मन गत करना जिस्सा कि न्यायिक आवश्यकतार्थे को बढ़ावा मिले और वह लागू की जा सकें।
 - शानेक प्रक्रपास च संवाओं स सम्बन्धित शुल्क के सम्बन्ध में आधार स्थापित करना।
 - माध्यम का चयन।
 - क्रिक ने हैं न तथा किसी एक तरह का माध्यम जिससे सेवा
 की जानी है (परम्यापत अथवा इलैक्ट्रानिक) का पक्ष लेना ।
 - अभियोग की सम्भावनाओं एवं लागत को कम करना।





- अप्राचिकारी विवाद निस्तारण तन्त्र उपलब्ध कराना जिसकी सेवा इच्छुक व्यक्ति हारा आह्वान किया जा सके।
- न ती उपक्रमो एव शासन के मध्य तथा विभिन्न निजी उपक्रमों के मध्य
 "भान भवाओं की सक्षिया एव अनुरक्षण हेतु वाछित सविदात्मक शर्ते, सेवा
 सम्बन्धी अनुबन्ध आदि उपलब्ध कराना।

ं १ र निए कि न्यायिक ढांचे का मठम किया जायेगा जो सूचना प्रौद्यांगिकी विकेश में पारदशिता सुनिश्चित करायेगा।

(क) शरक्षित ।

9

9

5

13

विवेश राज्य वेविम के कर भूगतान वाहन-प्रजीकरण इण्टरनेट भुगतान, .r. १८८ त राशन व १ पेसन बाहन चालक-लाइसेस, स्वास्थ्य विवरण ् ाः । भार काद एव ६० तमेट्रिक्स के उपयोग को शासन प्रोत्साहित करेगा। ेंय प्रमाण पत्रों को प्रोत्साहित करेगा तथा वर्तमान में विद्यामान .9 प्राधिकर । नथा पंनी सवाये उपलब्ध कराने वाली सर<mark>थाओं को इंगित</mark> रत कि इनके दाम पन सामान्य की पहुंच में रहे। सरकार का प्रयास र्न तर्ने के के कि स्थापना (PKI) का स्थापित किया जा सके, जिससे ा ऑस लाइन सुरक्षितता व्यक्तियन अभिप्रमाणिकरण एव रानिशिन हो २४३ । विभिन्न नीतियाँ प्रक्रियाओं सर्वर द्वेलफार्म, र कण रथना ताम जिल्ला बिन्दुओं का निर्धारण जो सार्वजनिक कुँ ती भ . उप ग 'PKI हेत् अ वश्यक होना के उपरान्त सरकार आवश्यक विश्वास पैदा फरने र अपन हो स हेती। रमधेजनिक कुँजी अवस्थापना (PKI) का तन्त्र एक ऐसी है से उक्षेग किया हा सक्या जो मात्र उपयोगकर्ता को पता होगी। एक ११२ में (बहु अध्यदः एकल एमाणिकरण प्राधिकारी) तथा अभिप्रमाणिकरण को २० : तमय बिन्द् पर लम्बाधित किया जायेग। परिशिष्टक विधान जो o र किए आवण्यक हं ना को भारत सरकार द्वारा लागू सूचना प्रौद्योगिकी। 🖑 🖺 🔐 े 🚅 २००० के अनुरूप तैयार कर स्थापित किया जायेगा ।



į

ŷ

g

ž

3

继

3

39

9

rigo.

3

Ü

100

'n.

diff

127

19

4

194

3

5

13

3

Ð

3

9

子明的



- भर र हारा प्रदान की जाने वाची ऐसी सेवाये जिनक लिए परिचय प्रबन्धन तन्त्र 60 की पर राजता हो के लिए स्मार्ट कार्ड अवस्थापना स्थापित की जायेगी। यह रा रंग पादा विनेक ध्रृंती अवस्थापना (PKI) के साथ एकीकृत की जायेगी एव भारत सरकार की अवधारण के अनुसार नागरिकों के बहु उपयोग के लिए उपलब्ध
- उन्देव ने सरकार ने पूर्व में ही अपने को शुन्य-सॉफ्टवेयर-नकल राज्य घोषित कर 61 अपनी आशय स्पष्ट कर दिया है।
- शारा । प्रमुक्ताओं की सुरक्षा हेत् सरकार यथा सन्भव सुरक्षित सरचना को लागू 62 ं र के अन्तर्गत फायरवाल दखल रोक तन्त्र प्रवेश नियत्रण व्यवसायिक निरम् । राज्या निपदा पुन प्रास्ति उपाय इत्यादि होंगे ।

प्रतिस्पर्द्धात्मक नीतियाँ

- पुनि 📺 ६७ नी चिरा तन है जो निजी क्षेत्र की प्रतिभागिता को सुनिश्चित करते 63 🔻 🤍 प्रतिसाद्ध मक रियातेर्गा वदा करती है। सरकार का उद्देश्य है कि कनोक अाचा विक्रा वय व से वह बच सके और स्वतन्त्र रहे इसलिए त रह भारता एवं विक्ताओं की एवं साथ कार्य करने हेत् प्रेरित किया जायेगा ा १ रन्द्र श्रेणाः की समय प्रथा की जा सक ऐसा करने पर नई TEN 1 1 के प्रधान के जिए जवश्यक रास्ता बना रहेगा। नागरिकों को सेवायें 🕝 न ने नि री % र ही प्र'तेभा'गेला को गलिशीलला प्रदान होगी।
- र के कि कि कि अप के अमाधनों यथा नेटवर्क मजबान केन्द्री राजस्व प्राते । रुपा सम्बन्धी प्रतिभू एव अनुबन्धी की उपलब्धता इत्सादि का अधिक से ু ু । प्राग শুশিখিলে हो ఆঠ। इस प्रकार ऐसे नीतिगत ढाँचो को बस दिया नः का जे तकनीकी अदासीन विनिर्दशों को तैयार करने में प्रेरक होगी और , र र ह नकनीकियां को विभिन्न समाधान तकनीकी - उदासीन विनिर्दशों के ,रज्र ' नैयार करने हेनु प्रोत्लाहित किया जा सकेगा, लुप्तप्राय होने वाली तकनीक से जान पाल सम्भावित नुकसान हेतु ऐसी नीति तैयार की जा सकेगी जिससे कि इस



ģ

9

S

炒

30

3

4

43

50

15

-

4

3

400 y

""

20

3



प्रकार की तकनीकी का विस्तार न हो सके एवं राज्य में ऐसे उत्पादक—संघों से बहाव कि में में सकेगा जो प्रतिव्यर्धात्मक कारकों को शनै हानै समाप्त कर सकते हैं।

- हासागर उता संप्टर मंजवान सेवाओं अवस्थापना प्रवन्धन इत्यादि हेतु विभिन्न र त र थ गकर्ना को प्रोत्सनहित किया जायेगा जिससे कि विभिन्न प्रकार की सेवायें इन सेवा--पोषणकर्ताओं से प्राप्त हो सकें।
- oe ए हारे विभाग मध्यवर्ती सहयोगी संस्थानों के साथ मिलकर खुली सरकार की कि अपना को जाताश करेगे और जहां सम्भव होगा वे उन्नत उपभोक्ता सेवाओं को जाताश करेगे और जहां सम्भव होगा वे उन्नत उपभोक्ता सेवाओं को जाताश करेंगे विभाग की जी की अपना वेंगे।

 उत्तर ह सहभागि ह निर्णय एक खुली सरकार की सम्भावनाओं की तलाश करेंगे न कि जाताश के मध्य प्रतिस्वाधी को समाप्त करेगी, जो नवीनता, उन्नत का उत्तर की समाप्त करेगी, जो नवीनता, उन्नत का उत्तर का स्थानित करती है, विभिन्न सेवाओं के स्थान का स्थानित करती है, विभिन्न सेवाओं के स्थान का स्थानित करती है, विभिन्न सेवाओं के स्थान का स्थानित करती है, विभिन्न सेवाओं के

होगी।

os ोल भ न्यूबन्ध हे (चयोगत संस्था का चयन तकनीकी एवं वित्तीय विश्लेषण जो ा अ त विभाव के भ रहार निया रेत किया जायेगा से होगा

VI- स्वीकारात्मक नीतियाँ

- 69 . मक नी नेवों को रणनीतिक मध्यवर्तन के प्रारम्भ से ही सुधारने की प्रक्रिया
 . मेर इस प्रोक्रेक में वाछित परिवर्तन प्रश्नम्भ का ढाँचा व साँचा रहता है।
 . प्राप्त र क गैरवलन के मध्यवर्तन। में व्यक्तिक्शिय समूह, सगठन एवं सगठन के व ना अ गर हात है जो सरकार एवं समुदाय के विभिन्न अवयवों को परिभाषित
 करते हैं।
- र का प्रयास रहेगा कि प्रत्यंक परिवर्तन रणनीति को सफल बनाने हेतु पाँच मुर्देश । वदा व्यक्ति निपूर्णला प्रेरणा संसाधन और क्रिया योजना – पर ध्यान केन्द्रित किया जाय।





- 71. किसी भी नवीन प्रयास को स्वीकार्य होने की स्थिति का अंकन करने हेतु समय-समय पर सर्वे किये जायेंगे। इस प्रक्रिया से सावधानी हेतु बिन्दु उभरेंगे जो रणनीति एवं क्रियान्वयन में किये जाने वाले आवश्यक सुधार हेतु ध्यानाकर्षण करेंगे।
- 72. शासन अपने कर्मचारियों को हर सम्भव प्रशिक्षण उपलब्ध करायेगी जिससे वह सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी की आधारभूत सुविधाओं का प्रभावी रूप से उपयोग करसकें। इससे उनकी दक्षता, पारदर्शिता एवं उत्पादकता में वृद्धि होगी।
- 73. शासन प्रत्यक्ष रूप से या गैर सरकारी संस्थाओं के समर्थन से विभिन्न सेवा प्रवाताओं जैसे कियोंस्क संवालक, शिक्षक, महिलायें, युवा वर्ग, वरिष्ठ नागरिक, विकलांग के लिये (आधारभूत सुविधाओं) के उपयोग हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम रचित है एवं क्रियान्वित करेगा।
- 74. शासन सुनिश्चित करेगा की सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के अग्रगमन ओरर उसके परिणाम स्वरूप शासन की व्यवस्था क्रम के स्वचलनीकरण से कर्मचारी में शेषता नहीं आयंगी।

VII- जन्मति नीतियां

- 75. उन्नति गीति से स्वीकृति रणनीति में वृद्धि आयेगी। व्यापक लोक—प्रचार के माध्यम से एवं ऑनलाईन लेन—देन को विशेष प्रलोभन से सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के उपयोग को शासन बस्तुत: प्रोत्साहित करेगा।
- 76. नवीन सेवाओं से होने वाली बचत और छोर प्रयोक्ता को होने वाला लाभ कैसे दिया जारो इस हेतु शासन निरीक्षण करेगा।

VIII- निष्पादक नीतियाँ

W.

77. ई-गवर्नेन्स परियोजनाओं को क्रियान्वित करने के लिये शासन परियोजना प्रबन्धन इकाई की स्थापना करेगा जो, स्वतंत्र सॉफ्टवेयर विकासक/ विक्रेता/ प्रणाली समाकलक/ पृष्ठ छोर के विमाग के साथ मिल कर नोडल एजेंसी (आई०टी०डी०ए०) के मार्गदर्शन में कार्य करेगी।





- 78. वस्ती अग्रगमन से स्वचलित कम्प्यूटरीकृत अग्रगमन पर स्थानान्तरण के लिये विभाग संतोषजनक परीक्षण के बाद एक निर्धारित दिनांक से कम्प्युट्रीकृत अग्रगमन पर कार्य आरम्भ कर दिया जाये। दस्ती और स्वचलित अग्रगमन साथ-साथ एक पूर्व परीभाषित समय सीमा में ही प्रयोग में रहेंगे।
- 79. प्रत्येक विमाग अपने पूर्व अभिलेख के अंकीकरण को निर्धारित करेगा। इसके साथ प्रावरथा का निर्धारण प्रत्येक विभाग करेगा इन सभी आंकड़ों के अंकीकरण की दशा में विभाग अपनी वरियता निर्धारित करेगा, इसके साथ आंकड़ों के अंकीकरण की हर दशा में विभाग एक अधिकारी निर्दिष्ट करेगा जो कि बाह्य/ आन्तरिक स्रोत से प्राप्त आंकड़ों की पुष्टि करेगा।
- 80. ई—गवर्नेन्स परियोजनाओं के आरम्भ के बाद विभागाध्यक्ष सीस एवं संस्तुति पर पूर्ण आख्या प्रस्तुत करेंगे।

(अ) सूचना प्रौद्योगिकी सलाहकार समिति

- 81. उत्तरांचल सरकार ने एक उच्च स्तरीय समिति (Core Group on IT) का गठन मुख्य सिंदव की अध्यक्षता में किया है। इस समिति के सदस्य औद्योगिक विकास आयुक्त, वन एवं ग्राम्य विकास आयुक्त, प्रमुख सिंदव (कार्मिक), सिंदव (वित्त), सिंदव (नियोजन) तथा सिंदव (सूचना प्रौद्योगिकी) सदस्य सिंदव सेयोजक होंगे।
- 82. सूधना प्रौद्योगिकी विकास एजेंसी (आई०ई०टी०डी०ए०) सूचना प्रौद्योगिकी के समस्त नवीन—प्रवासों हेतु नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करेगी।

4

tos low ryela





संलग्नक 'अ'

सूचना प्रौद्योगिकी (जैसा की नवीन औद्योगिक नीति 2003 में इंगित है):

पूजना प्रौद्योगिकी सम्बन्धित क्षेत्राओं तथा हार्डवेयर विकास हेतु राज्य प्राकृतिक रूप से प्राथ्योगेकता याला स्थान रहा है क्योंकि इनके उत्पादन हेतु पूर्व आवश्यकताएं प्राकृतिक रूप से उपलब्ध हैं।

- सूचना श्रौद्योगिकी एवं सम्बन्धित सेवाओं को उद्योग का दर्जा दिया गया है।
- उत्तरांचल में देहरादून में एस.टी.पी.आई. एवं अन्य स्थानों पर प्रस्तावित अर्थ स्टेशन की स्थापना के माध्यम से तीव्र गति संयोजिता उपलब्ध कराई जायेगी।
- देहराबून में एक समर्पित सूचना प्रौद्योगिकी पार्क स्थापित किया जा रहा है तथा राज्य के यूसर क्षेत्रों में भी खूचना प्रौद्योगिकी पार्क स्थापित करना प्रस्तावित है।
- 😕 भूमि-उपयोग उपयोग व सूमि रूपान्तरण प्रक्रिया व शुल्क को युक्तिसंगत किया जायेगा।
- इन सेवाओं को जनहित सुविधाओं का वर्जा दिया जायेगा तथा उचित नियंत्रण, सुविधाएं एथा अवस्थापना के साथ महिलाओं को तीन पालियों में चौबीस घंटे काम करने की छूट प्रदान की जायेगी।
- पोणित सूबना प्रौद्योगिकी पार्क इण्डस्ट्रियल स्टेट में लगने वाले जनस्टर सैट्स को विधुत कर से मुक्त रखा जायेगा।
- सूचना प्रोचोगिकी पार्क में स्थापित की जा रही इकाईयों को स्टाम्प शुल्क में रियायत दी जारोगी।
- राज्य सरकार सभी सॉफ्टवेयर इकाईयों को 2 एमबीपीएस वैण्डविड्थ एक वर्ष तक निम्न प्राविधानों के अन्तर्गत नि:शुल्क उपलब्ध कराई जायेगी:—
 - (i) हार्डवेयर तथा इसके लगने की लागत को आवेदक द्वारा वहन किया जायेगा।
 - (ii) बैंडविड्थ अहस्तान्तरणीय व "नॉन-शेयरिंग" होगी।
 - (iii) उद्यमी/ इकाई बी.एस.एन.एस./वी.एस.एन.एस./एस.टी.पी.आई. अथवा किसी निजी सेवा-प्रदाता से बैडविड्थ संयोजिता प्राप्त कर सकेगा, परन्तु वैंडविड्थ की लागत एस.टी.पी.आई./ बी.एस.एन.एल. द्वारा निर्धारित दर के अनुसार होगी।





(iv) स्योजकता उपलब्ध कराने हेतु निम्न उपलब्ध होंगे:--

(क) श्रेणी— 1 कॉल सेन्टर्स 25 सीटर

-

512 के.बी.पी.एस.

50 सीटर

_

1 एम.बी.पी.एस.

100 सीटर

2 एम.बी.पी.एस.

(ख) श्रेणी— 2 ऑफ—लाईन बी,पी.ओ. एवं ऐसे अन्य संस्थापनः

उपरोक्त का एक चौथाई

(ग) श्रेणी— 3 ऑन—लाईन बी.पी.ओ. एवं ऐसे अन्य संस्थापनः

उपरोक्त का आधा

(घ) श्रेणी- 4 उपरोक्त कार्यकलापों का मिश्रण:

प्रथम श्रेणी में वर्णित अधिकतम सीमा तक

- (v) साईबर कैफें / जनता के मनोरंजन हेतु संस्थानों के लिए उपरोक्त छूट लागू नहीं होगी।
- (vi) इस छूट हेतु प्रारम्भिक तिथि, संयोजिता के प्रथम दिन से मानी जा येगी तथा यह दुविधा दुकडों में उपलब्ध नहीं अपितु एक वर्ष तक लगातान लेनी होगी।

by

5 5 5 C S

Inh 4/171.